



जनवरी 20, 2024

दीक्षांत समारोह का संबोधन
मुख्य अतिथि



प्रो. सुकान्ता कुमार सेनापति
कुलपतिश्री

श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, वेरावल



जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय
जूनागढ़ - ३६२००१
गुजरात

मुख्य अतिथि

प्रो. सुकान्ता कुमार सेनापति

कुलपतिश्री, श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, वेरावल

गुजरात के माननीय राज्यपाल एवं जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय के कुलाधिपतिश्री आचार्य देवव्रतजी, गुजरात सरकार के माननीय कृषि, पशुपालन, गौपालन एवं मत्स्य पालन मंत्री श्रीराघवजीभाई पटेल, जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. वी.पी. चोवटिया, कुलसचिव डॉ. वाई.एच. घेलानी, गुजरात राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों के माननीय कुलपति, प्रबंधन बोर्ड एवं शैक्षणिक परिषद के सदस्यगण, आमंत्रित अतिथिगण, विद्वान संकाय सदस्यगण, प्रिय छात्रगण, प्रेस एवं मीडिया के प्रतिनिधिगण, देवियो एवं सज्जनों।

जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय के २०वें दीक्षांत समारोह के इस महत्वपूर्ण अवसर पर आज यहाँ उपस्थित होना मेरे लिये सम्मान और सौभाग्य की बात है। आजका दिन इस प्रतिष्ठित संस्थान की यात्रा में एक महत्वपूर्ण और अहम पल है। पिछले दो दशकों में, जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय न केवल गुजरात में बल्कि पूरे देश में कृषि शिक्षा, अनुसंधान और कृषि विकास को आगे बढ़ाने में अग्रसर रहा है। यह २०वां दीक्षांत समारोह दो दशकों की अकादमिक उत्कृष्टता, समर्पित सेवा और कृषि क्षेत्र में अनगिनत योगदान का उत्सव है। प्रत्येक वर्ष, यह संस्थान मजबूत होता जा रहा है और आज का समारोह जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय की शक्ति, स्थिरता और भविष्य की उम्मीदों का प्रतीक है।

जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय के दूरदर्शी कुलपति डॉ. वी.पी.चोवटिया को हार्दिक बधाई देता हूँ और उन्हें इस गर्मजोशी भरे निमंत्रण तथा शिक्षा और छात्रों के कल्याण और उत्थान के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने इन युवा दिमागों को न केवल ज्ञान बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना पैदा करते हुए एक ठोस आधार प्रदान किया है। वे इस संस्थान के सम्मानित शिक्षक, कर्मचारियों और छात्रों के लिए उर्जा का स्रोत हैं। उनके समर्पण, जोश और ज्ञान की निरंतर खोज ने इन स्नातकों को तराशा है और उन्हें आज के नेतृत्व कौशल के रूप में आकार दिया है।

मैं उन सभी छात्रों को बधाई देता हूँ जिन्हें इस प्रतिष्ठित संस्थान द्वारा स्नातक, स्नातकोत्तर या डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान की गई है। मुझे यकीन है कि आप सभी वर्षों की कड़ी मेहनत, दृढ़ता और समर्पण से बनी विरासत को आगे बढ़ाएँगे। आज, जब आप चुनौतियों और अवसरों से भरी दुनिया में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं, तो याद रखें कि यह केवल एक अध्याय का अंत नहीं है, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। आप स्नातकों की एक गौरवशाली परंपरा का हिस्सा हैं, जिन्होंने कृषि और उससे परे के क्षेत्र में बदलाव लाया

है। मुझे सभी गौरवान्वित माता-पिता को भी बधाई देते हुए खुशी हो रही है और मैं कहना चाहता हूँ कि उनके त्याग, प्रोत्साहन और अपने बच्चों की क्षमता में अटूट विश्वास ने इस क्षण को संभव बनाया है।

जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय के २०वें दीक्षांत समारोह का जश्न मनाते हुए, आइए हम विश्वविद्यालय की समृद्ध और स्वस्थ शक्तियों को पहचानने के लिए कुछ समय निकालें। विश्वविद्यालय प्रयोगशाला और क्षेत्र अनुसंधान को एकीकृत करने वाला एक मजबूत मंच प्रदान करता है, जो स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट छात्रों के लिए व्यावहारिक और शोध के अवसर प्रदान करता है। जे.ए.यू. के पास विभिन्न संकायों में शिक्षण, अनुसंधान और विस्तार गतिविधियों के लिए उच्च योग्य एव विद्वान शिक्षक हैं।

दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि कृषि ही वह क्षेत्र है, जहाँ आप अपना उज्वल भविष्य बना सकते हैं। भारत में कृषि विकास में अपार संभावनाएँ हैं। हालाँकि, मैं आपको वर्तमान में कृषि के लिए चुनौतियों से अवगत कराता हूँ, जिन्हें आप अपने भविष्य की राह में संभावनाओं के रूप में देख सकते हैं। कृषि क्षेत्र को सिकुड़ती भूमि और जल संसाधनों से देश की बढ़ती आबादी का भरण-पोषण करना है। बढ़ती जनसंख्या, जीवन स्तर में वृद्धि, औद्योगीकरण, बुनियादी ढाँचे के विकास के कारण अत्यधिक दबाव में प्राकृतिक संसाधनों का हास हो रहा है। रासायनिक खादों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, मिट्टी का कटाव, लवणता और पोषक तत्वों की कमी प्रमुख मुद्दे हैं।

देश का ६०% से अधिक क्षेत्र वर्षा आधारित खेती के अंतर्गत है, जो सीमित वर्षा और वर्षा ऋतु पर निर्भरता के कारण पानी की तीव्र कमी का सामना करता है। भूजल कम होता जा रहा है और इसकी गुणवत्ता दिन-प्रतिदिन खराब होती जा रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण, लगातार अनियमित वर्षा, सूखा, बाढ़, तापमान और कृषि जल संसाधनों और पारिस्थितिक संतुलन के लिए गंभीर जोखिम पैदा करते हैं। बढ़ती आबादी के कारण औसत खेत का आकार छोटा होता जा रहा है, जिससे किसानों के लिए मशीनीकरण और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाना मुश्किल हो रहा है। किसान, अपर्याप्त बाजार पहुंच, बिचौलियों और फसल की कीमतों में उतार-चढ़ाव से जूझ रहे हैं। फल, सब्जियां और डेयरी जैसी जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं का उत्पादन करने वाले किसान अक्सर खराब भंडारण और परिवहन बुनियादी ढाँचे के कारण नुकसान उठाते हैं। अपर्याप्त ग्रामीण बुनियादी ढाँचे जैसे कि सड़कें, कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान का कारण बनती हैं। बेहतर अवसरों की तलाश में बढ़ी संख्या में ग्रामीण युवा शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन कर रहे हैं, जिससे कृषि में वृद्ध कार्यबल रह गया है।

दोस्तों, मिट्टी और पानी कृषि के लिए दो बुनियादी संसाधन हैं। हालाँकि, वर्तमान में, दोनों संसाधनों का अत्यधिक दोहन और क्षरण हो रहा है। इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए, संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने विश्व मृदा दिवस-२०२४ का विषय मिट्टी की देखभाल: माप, निगरानी, प्रबंधन चुना है। मानव के लिए कृषि के महत्व ने संयुक्त राष्ट्र को कुल १७ एसडीजी में से ६ वें एसडीजी (सतत विकास लक्ष्य) को सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और टिकाऊ प्रबंधन सुनिश्चित करना के रूप में चुना। वैज्ञानिक, टेक्नोक्रेट, नीति निर्माता और ब्यूरोक्रेट्स इस बात की चेतावनी देते हैं कि अगला विश्व युद्ध पानी के लिए होगा। जब पानी की कमी होगी, तो समुदायों और देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है। दुनिया भर में ३ बिलियन से अधिक लोग राष्ट्रीय सीमाओं को पार करने वाले पानी पर निर्भर हैं जलवायु परिवर्तन के प्रभाव बढ़ने और जनसंख्या वृद्धि के कारण, हमारे सबसे कीमती संसाधन की रक्षा और संरक्षण के लिए देशों के भीतर और उनके बीच एकजुट होने की तत्काल आवश्यकता है। इसने 'शांति के लिए जल' की थीम पर विश्व जल दिवस-२०२४ के उत्सव के माध्यम से मानव जाति के हर क्षेत्र में पानी के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए पूरी दुनिया को जागरूक करने के लिए मजबूर किया है। जब हम पानी पर सहयोग करते हैं, तो हम एक सकारात्मक प्रभाव पैदा करते हैं सदभाव को बढ़ावा देते हैं, समृद्धि पैदा करते हैं और साझा चुनौतियों के लिए मजबूती बनाते हैं।

मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि भारत सरकार ६ वें सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति कर रही है। विभिन्न पहलों में से राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन एक प्रमुख प्रयास के रूप में सामने आया है। भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (बीपीकेपी) योजना का कुल परिव्यय छह वर्षों (२०१९-२० से २०२४-२५) की अवधि के लिए ४६४५.६९ करोड़ रुपये है और इसे केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) दिशानिर्देशों के अनुसार मांग आधारित आधार पर कार्यान्वित किया गया है। यह मिशन एक वैकल्पिक कृषि प्रणाली को बढ़ावा देता है जो बाहर से खरीदे गए इनपुट पर निर्भरता को कम करता है, लागत कम करता है, किसानों की आय बढ़ाता है और पशुधन और स्थानीय संसाधनों का लाभ उठाते हुए एकीकृत कृषि-पशुपालन मॉडल को प्रोत्साहित करता है। प्राकृतिक खेती के लाभ हैं: बेहतर उपज; किसानों की आय में वृद्धि; उत्पादन की लागत को कम करना; जलवायु अनुकूल कृषि; बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करना; रोजगार सृजन; सिंथेटिक रासायनिक इनपुट के उपयोग को खत्म करना; पर्यावरण संरक्षण; पानी की खपत में कमी; मृदा स्वास्थ्य और पशुधन स्थिरता को पुनर्जीवित करता है।

इस मिशन के तहत १०.०५ लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को प्राकृतिक खेती के अंतर्गत लाया गया है, जिससे १७ राज्यों के २८ लाख से अधिक किसान लाभान्वित

हुए हैं। इनमें आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, केरल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु प्रमुख हैं। उल्लेखनीय रूप से, गुजरात ३.१७ लाख हेक्टेयर प्राकृतिक खेती के साथ देश में पहले स्थान पर है, जबकि आंध्र प्रदेश २.९ लाख हेक्टेयर के साथ दूसरे स्थान पर है। यह उपलब्धि गर्व का विषय है और भारत में टिकाऊ खेती के तरीकों को अपनाने की बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाती है। इस कवरेज के अलावा, भारत सरकार ने बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाली गंगा नदी के दोनों किनारों पर ५ किलोमीटर की सीमा पर १.५ लाख हेक्टेयर को बढ़ावा दिया है।

दोस्तों, आज कृषि क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा जलवायु परिवर्तन है। मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि गुजरात राज्य भारत में शमन अनुकूलन और सतत विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने वाले विभिन्न कार्यों को करने में अग्रणी है; गुजरात २००९ में जलवायु परिवर्तन विभाग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य है। राज्य की जलवायु कार्य योजना अक्षय ऊर्जा, जल संरक्षण, टिकाऊ कृषि और शहरी स्थिरता पर केंद्रित है। राज्य ने स्वच्छ ऊर्जा में करीब ३० गीगावाट की स्थापित क्षमता का निर्माण किया है, जिसमें सौर क्षमता १४.७ गीगावाट है। राज्य की कुल छत सौर ऊर्जा क्षमता ३.५ गीगावाट है। गुजरात में भारत के लगभग दो-तिहाई आवासीय सौर ऊर्जा प्रणालियाँ हैं। अभी हाल ही में, गुजरात सरकार ने ₹ १७७ करोड़ आवंटित करके सरकारी भवनों पर सौर छत प्रणाली स्थापित करने की पहल शुरू की है। ४८ मेगावाट सौर उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। राज्य ने अपनी अक्षय ऊर्जा नीति २०२३ पेश की। नीति का लक्ष्य २०३० तक ६४००० हेक्टेयर बंजर भूमि पर १०० गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता का विकास करना है और इसका लक्ष्य ५ ट्रिलियन रुपये का निवेश आकर्षित करना है। गुजरात अक्षय ऊर्जा, विशेष रूप से सौर और पवन ऊर्जा में अग्रणी है। यह ३० गीगावाट क्षमता वाला दुनिया का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा पार्क भी बना रहा है। यह पार्क, जिसमें सौर और पवन ऊर्जा दोनों का मिश्रण होगा, हर साल ५ मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगा। गुजरात के चारणका में सौर पार्क (६०० मेगावाट) और रूफटॉप सौर प्रणाली जैसी पहल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।

सूर्य शक्ति किसान योजना ने एक लाख किसानों को सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा उत्पन्न करने और ग्रिड को अधिशेष बिजली बेचने में सक्षम बनाया। गुजरात पवन ऊर्जा उत्पादन में शीर्ष राज्यों में से एक है, जिसकी स्थापित क्षमता ९,००० मेगावाट से अधिक है, जो भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों में महत्वपूर्ण योगदान देता है। गुजरात अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं में अग्रणी है, जिसमें खंभात की खाड़ी में प्रस्तावित १,००० मेगावाट का अपतटीय पवन फार्म भी शामिल है। गुजरात हरित हाइड्रोजन उत्पादन के केंद्र

के रूप में उभर रहा है, जो उद्योगों के लिए स्वच्छ ईंधन का उत्पादन करने के लिए अपनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लाभ उठा रहा है। गुजरात की नवीकरणीय ऊर्जा पहलों ने कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी लाने में योगदान दिया है, जो अन्य राज्यों के लिए मानक स्थापित करता है।

यह स्वीकार करना बेहद चिंताजनक है कि भारत में दुनिया की १७% आबादी रहती है, लेकिन इसके पास वैश्विक मीठे पानी के संसाधनों का केवल ४% ही है। यह बेमेल एक गंभीर चुनौती पैदा करता है: स्थायी रूप से आर्थिक विकास प्राप्त करते हुए आबादी की जरूरतों को पूरा करना। यह स्पष्ट असंतुलन स्थायी जल प्रबंधन और संरक्षण प्रयासों की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। इस गैर-नवीकरणीय संसाधन को अर्थव्यवस्था के लिए जो चीज अधिक महंगी बनाती है, वह यह है कि जल कुप्रबंधन २०५० तक इसके सकल घरेलू उत्पाद को लगभग ६% तक कम कर सकता है। गुजरात में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता सन् १९५१ में ३१३१ घन मीटर से २०२४ में ७७० घन मीटर तक लगातार गिरावट का प्रदर्शन कर रही है। इसके २०६० में मात्र ५८५ घन मीटर होने का अनुमान है। हालांकि, गुजरात एक ऐसा भारतीय राज्य है जो अपने जल संकटों को सफलतापूर्वक दूर करने में कामयाब रहा है आज, नीति आयोग द्वारा दिए गए समग्र जल प्रबंधन सूचकांक के अनुसार, यह देश में जल प्रबंधन प्रथाओं के मामले में पहले स्थान पर है। सरकार २०४७ तक गुजरात के लोगों के लिए प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता को दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध है। गुजरात में वर्तमान में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता ७७० घन मीटर/वर्ष है, जिसे २०४७ तक बढ़ाकर १,७०० घन मीटर करने का अनुमान है।

जैसा कि हम जानते हैं कि भारत का कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार में एक प्रमुख योगदानकर्ता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजरा उत्पादक है, और फलों और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगभग ७.०३ मिलियन लोगों को रोजगार देता है। भारत का प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात २०१९ में ४.४५ बिलियन डॉलर से बढ़कर २०२४ में ४४ बिलियन डॉलर हो गया है। सरकार ने २०२२-२७ की अवधि के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के लिए १०९ बिलियन डॉलर अलग रखे हैं।

हालाँकि, मेरे विचार में, भारत में कृषि क्षेत्र के लिए विभिन्न नीतियों के कार्यान्वयन के माध्यम से कुछ समस्याओं के बावजूद दोनों पक्षों के लिए जीत की स्थिति हो सकती है;

- सिंचाई परियोजना के प्रदर्शन को नहर लाइनिंग के माध्यम से या पीआईएन (दबाव सिंचाई नेटवर्क प्रणाली) को अपनाकर जल वितरण नेटवर्क को मजबूत करके

इसकी क्षमता को बढ़ाया जाना चाहिए।

- कुछ राज्यों में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन उपलब्ध हैं, जिन्हें भारत के जल की कमी वाले राज्यों में स्थानांतरित किया जा सकता है। ऐसे बुनियादी ढांचे के लिए निवेश को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- देश के तटीय क्षेत्र में बहने वाली सभी नदियों को जोड़ने वाले चैनल लिंक को समुद्र तट से ४०-५० किमी की संभावित दूरी पर खोदा जाना चाहिए ताकि समुद्री जल के प्रवेश को रोका जा सके, भूजल संसाधनों और इसकी गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके।
- वर्षा आधारित क्षेत्रों में कृषि पद्धतियों, कंटूर मेंडबंदी, मेड़ एवं फरो प्रणाली आदि के माध्यम से जल संचयन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- सरकार को बंजर/परती भूमि के साथ-साथ श्रृंखलाबद्ध जलधाराओं पर जल संचयन-सह-भूजल पुनर्भरण संरचनाओं को अपनाना चाहिए।
- जल उपयोग कुशल सिंचाई विधियों को अपनाने के साथ-साथ जल प्रबंधन रणनीतियों के नए आयामों जैसे मल्टिचिंग, फर्टिगेशन, उपसतही सिंचाई, स्पंदित ड्रिप सिंचाई, अल्प सिंचाई, वातित सिंचाई आदि को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- बदलती जलवायु में फसलोकी ऐसी किस्मों को अपनाया जाना चाहिए जो मौसम, वर्षा आदि की चरम स्थितियों को सहन कर सकें।
- सरकार को राज्य में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए समस्याग्रस्त मृदाओं के सुधार को बढ़ावा देना चाहिए।
- मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और प्रदूषण को कम करने के लिए किसानों को सहाय और प्रशिक्षण देकर प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों को उच्च बिक्री मूल्य प्राप्त करने के लिए अलग से बाजार उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
- मृदा उर्वरता और कीट प्रबंधन में सुधार के लिए फसल चक्र और अंतरफसल के माध्यम से फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना चाहिए।
- प्रशिक्षण कार्यक्रमों और क्षेत्र प्रदर्शनों के माध्यम से कृषि ज्ञान और आधुनिक प्रौद्योगिकियों तक पहुंच बढ़ाने के लिए विस्तार सेवाओं का विस्तार और सुदृढीकरण करना चाहिए।
- किसानों की सहकारी समितियों/एफपीओ को मजबूत बनाना ताकि सौदेबाजी की शक्ति और बाजारों तक पहुंच में सुधार हो सके। फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए पर्याप्त भंडारण सुविधाओं और कोल्ड चेन के माध्यम

से बाजार के बुनियादी ढांचे में सुधार करना। किसानों के लिए उचित रिटर्न सुनिश्चित करने के लिए एमएसपी योजनाओं और प्रत्यक्ष बाजार पहुंच प्लेटफार्मों के माध्यम से उचित मूल्य निर्धारण तंत्र को लागू करना चाहिए।

- कर्ज में डूबे किसानों पर बोझ कम करने के लिए विकल्पों का पुनर्गठन करके किसानों की परेशानी को कम किया जाना चाहिए। विकेंद्रीकृत कृषि उद्योगों, ग्रामीण उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से गैर-कृषि आय के अवसरों को बढ़ाकर आजीविका विविधीकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- स्वास्थ्य देखभाल, बीमा और अन्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों तक पहुंच का विस्तार करके किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत किया जाना चाहिए।
- उद्योगों, वाणिज्यिक और मनोरंजक गतिविधियों के लिए बुनियादी ढांचे को बंजर भूमि या समस्याग्रस्त मिट्टी में प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

दोस्तों, आज हम मानव जीवन के हर क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की शक्तियों का अनुभव कर रहे हैं। वास्तव में, अन्य क्षेत्रों की तरह ही एआई के उपयोग में कृषि भी पीछे नहीं रहेगी। अप्रत्याशित मौसम, पानी की कमी, कीटों के प्रकोप और श्रम की कमी जैसी प्रमुख चुनौतियों का समाधान करके एआई भारत में कृषि में क्रांति ला रहा है। एआई-संचालित समाधान खेती के तरीकों में सटीकता, दक्षता और स्थिरता को बढ़ाते हैं। भारत जैसे देश के लिए, जहाँ कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, एआई का उपयोग संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित कर सकता है, फसल की पैदावार में सुधार कर सकता है और लागत को कम कर सकता है, जिससे किसानों को सीधे लाभ होगा और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी। इसके अतिरिक्त, एआई जलवायु परिवर्तन के जोखिमों को कम करने और स्मार्ट खेती तकनीकों को बढ़ावा देने में सहायता करता है, जिससे किसान सोच-समझकर निर्णय ले पाते हैं। भारत में कृषि में एआई को अपनाने की बढ़ती प्रवृत्ति इस क्षेत्र को उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला दक्षता से लेकर बाजार तक पहुँच और लाभप्रदता तक बदलने की इसकी क्षमता को रेखांकित करती है।

कृषि में एआई अनुप्रयोगों के संभावित क्षेत्र इस प्रकार हो सकते हैं ;

- सटीक खेती के लिए ड्रोन, सेंसर और एआई एल्गोरिदम का उपयोग करके फसल के स्वास्थ्य की निगरानी करना।
- रोपण और कटाई के मार्गदर्शन के लिए सटीक मौसम पूर्वानुमान हेतु उन्नत मॉडल
- एआई-सक्षम मृदा परीक्षण और पोषक तत्व अनुशांसाएँ।

- जल उपयोग को अनुकूलित करने के लिए एआई का उपयोग करने वाली स्मार्ट सिंचाई प्रणालियाँ।
- छवि पहचान और एआई मॉडल के माध्यम से शीघ्र पता लगाना।
- खेत से बाजार तक दक्षतापूर्ण पहुंच के लिए रसद व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना।
- बेहतर निर्णय लेने के लिए फसल की कीमतों की भविष्यवाणी करने हेतु एआई उपकरण।
- रोपण, निराई और कटाई कार्यों के स्वचालन के लिए एआई-संचालित रोबोटों की तैनाती।
- ऋण और फसल बीमा के लिए एआई-आधारित मूल्यांकन।
- पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए संसाधनों का अनुकूलन।

आप इसे एक चुनौती और क्षमता के रूप में लें और अपना भविष्य बनाएं। मुझे यकीन है कि ये सभी एआई अनुप्रयोग आने वाले दिनों में आप जैसे प्रतिष्ठित जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय से स्नातक कृषि टेक्नोक्रेट द्वारा संभव हो सकते हैं। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय को भारत के सभी राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में ७वां रैंक और एजुकेशनवर्ल्ड, इंडिया हायर एजुकेशन रैंकिंग २०२३-२४ द्वारा राज्य में दूसरा रैंक दिया गया है। साथ ही, जे.ए.यू. गुजरात का एकमात्र सरकारी विश्वविद्यालय है जिसे द इंडिया टुडे रैंकिंग-२०२४ द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर ३१ वां स्थान दिया गया है। इनके अलावा, हाल ही में गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क ने जेएयू को लगातार चौथी बार ५ -स्टार रेटिंग प्रदान की है। इस प्रकार, जे.ए.यू. के मुकुट में तीन और पंख जुड़ गए। इस साझेदारी में कृषि, बागवानी और कृषि इंजीनियरिंग में दोहरे स्नातक और अनुस्नातक कार्यक्रम शामिल हैं। यह साझेदारी कृषि शिक्षा और अनुसंधान में नवाचार और उत्कृष्टता लाने वाले वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जे.ए.यू. की अटूट प्रतिबद्धता को उजागर करती है। यह सहयोग कृषि शिक्षा और वैश्विक साझेदारी में उत्कृष्टता के लिए जे.ए.यू. की प्रतिबद्धता को पुष्ट करता है। मुझे यकीन है कि आप माननीय कुलपति डॉ. वी.पी.चोवटियाजी द्वारा आपको वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के लिए किए गए इन श्रमसाध्य प्रयासों के परिणामों का लाभ उठाएंगे।

जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय के २०वें दीक्षांत समारोह में अपनी उपलब्धियों के लिए उपाधियां और पदक प्राप्त करने वाले सभी अभिभावकों और विद्यार्थियों को बधाई देता हूं।

जय हिंद, जय भारत,

धन्यवाद!

